सामयिक

भारत के लिए हिना के मायने

प्रभात कुमार राय

पाकिस्तान की नई नवेली विदेशमंत्री हिना रब्बानी की आतिशी दौरे के दौरान उनकी कूटनीतिक कुशलता की तो कुछ कम ही चर्चा हुई, किंतु उनके शानदार शाही अंदाज और उनकी फैशनपरस्ती की चकमक से भारतीय मीडिया सराबोर रहा। हिना रब्बानी की शख्सियत में ऐसा क्या राज निहित है कि एक से बढ़कर एक कूटनीतिक सियासतदानों में मध्य पाकिस्तानी हुकूमत ने हिना रब्बानी को इस बेहद नाजुक और मुश्किल वक्त में अपना विदेश मंत्री बनाया। रब्बानी जैसी अल्ट्रा मॉडर्न और बेहद फैशनेबल मोहतरमा को विदेश मंत्री नॉमीनेट करके पाकिस्तानी हुकूमत अमेरिका और समस्त पश्चिमी मुल्कों को यह पैगाम देना चाहती है कि पाक हुकूमत, कट्टर मुल्लावाद के असर से निजात पा चुकी है और उसकी बागडोर अब पश्चिमी तर्ज पर तालीमयाफ्ता राजनेताओं के हाथों में है। आंतकवाद के साथ गहन संलिप्तता के सबूतों के कारण अमेरिकन सीनेटर टैड पौई ने पाकिस्तान को प्रदान की जाने वाली पंद्रह हजार करोड़ की आर्थिक और सैन्य इमदाद को रोकने के लिए एक प्रस्ताव सीनेट में पेश किया। अमेरिकन नाराजगी से पाकिस्तान की जान जोखिम में है। मैडम हिना रब्बानी को इसीजिए विदेश मंत्री बनाया गया, जिससे वे वेस्टर्न अंदाज से अमेरिका और वेस्ट को कूटनीतिक तौर पर संभालें।

हिना रब्बानी का भारत दौरा और अधिक कामयाब साबित हो सकता था, यदि वह भारत में कदम रखते ही सर्वप्रथम कश्मीर के हुर्रियत लीडरान से मुलाकात करने की गंभीर गलती न करतीं। इस मुलाकात से यह संदेश चला गया कि भारत में पाकिस्तानी हुक्मरान अब भी खुले आम कश्मीर के अलगावादियों को तरजीह देते हैं। हिना रब्बानी से ठीक पहले अमेरिकन विदेश मंत्री मैडम हिलेरी क्लिंटन की भारत यात्रा खत्म हुई। इस यात्रा के दौरान ही अमेरिका में गुलामनबी फई सरीखे महत्वपूर्ण आईएसआई एजेन्ट की गिरफ्तारी का खुलासा किया गया। फई की गिरफ्तारी के खुलासे की इस अमेरिकन टाइमिंग में विशिष्ट अर्थ निहित रहा। अमेरिकन हुकूमत ने इस वक्त भारत को यह संदेश प्रदान करना चाहा कि कश्मीर जेहाद के प्रति उसकी नीति पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी है। अमेरिका अब अपनी सरजमीं पर भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश आयद करेगा। इस नीतिगत परिवर्तन के तहत ठोस अमेरिकन राष्ट्रीय हित निहित रहे हैं। 9-11 को संगीन जख्म झेलने के पश्चात अमेरिका ने कथित कश्मीर जेहाद के प्रति अपना रवैया आमूल-चूल तौर पर तब्दील किया और उसे आजादी की जंग करार देना बंद किया। सर्वविदित है कि 1988 में सोवियत साम्यवाद बनाम जेहादी जंग के दौरान सीआईए और आईएसआई ने संयुक्त तौर पर कश्मीर में अलगाव को हवा देना शुरू किया था। 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप के पश्चात, एक बार पुनः पाकिस्तान अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी बना। अमेरिका ने पाकिस्तान को भरपूर हथियार और डालर फराहम कराए, जिनका इस्तेमाल आईएसआई कश्मीर में कथित आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए करती रही।

भारतीय कूटनीतिकारों ने भी किसी हद तक अमेरिकन हुकूमत को यह समझाने में कामयाबी प्राप्त की कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे आईएसआई है, जो अमेरिका से मिलने वाली इमदाद से ही सब कुछ करा रही है। अमेरिकन संसद ने कैरी-लॉगर बिल को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत आजकल एक उच्च स्तरीय अमेरिकन कमेटी, पाकिस्तान को प्रदान की जाने वाली संपूर्ण दौलत और हथियारों के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखती है।

एक तथ्य को स्पष्ट रुप से समझ लेना चाहिए कि अमेरिका के लिए न तो पाकिस्तान महत्वपूर्ण रहा है और न ही भारत, उसके लिए सर्वोपरि तौर पर महत्वपूर्ण हैं, तो उसके ठोस राष्ट्रीय हित और उसके निजी सरोकार। यह ठीक है कि पाकिस्तान कोल्ड वार के दौर में अमेरिका का विश्वस्त सहयोगी रहा, किंतु अब हालात पूरी तरह परिवर्तित हो चुके। वर्तमान ऐतिहासिक दौर में अमेरिका की राष्ट्रीय व्यथा-कथा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से अविरल जूझना और अंततः उसको खत्म करने तक कतई शिथिल न होना ही लिखा है। भारत और अमेरिका की राष्ट्रीय पीड़ा के झंझावत एकरूप हो उठे हैं, अतः भारत को भी अपने ठोस राष्ट्रीय हितों के सर्वोपरि रखते हुए, अमेरिका के प्रति अपने ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों से उठकर सोचना समझना होगा। आतंकवादी विचारधारा से प्रेरित कोई भी इंसान लोकतांत्रिक राष्ट्रों का कट्टर शत्रु रहा है, इस तथ्य को इतिहास ने स्वयं सिद्ध कर दिखाया। सोवियत साम्यवाद के विरुद्ध जिन छोटे आतंकी प्रेतों को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने विराट दैत्याकार रूप प्रदान किया, अंततः वे सभी दैत्य अपने सृजनकर्ताओं पर ही कहर बनकर टूट पड़े। इन आतंकवादी दैत्यों से समूची मानवता को मिलकर ही युद्ध करना होगा। राजनीति और कूटनीति की बिसात पर कभी कोई स्थाई तौर पर दुश्मन अथवा दोस्त नहीं हुआ करता, इस कुटिल बिसात पर यदि कोई स्थाई मित्र रहा है तो वह हैं ठोस राष्ट्रीय हित।

भारतीय लोगों की तरह ही पाकिस्तान के लोग भी आतंकवाद से त्रस्त रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान यदि अपनी कश्मीर ग्रंथि से मुक्ति हासिल कर लें, तो भारत-पाक संबंध सामान्य हो सकते हैं। पाकिस्तान के तो वजूद को ही आतंकवाद ने गंभीर खतरे में धकेल दिया है। पाकिस्तान की अफगान सरहद के उत्तर पश्चिम इलाके पूर्णतः आतंकवाद के चंगुल मे आ चुके हैं और कड़ी कोशिश के बावजूद पाकिस्तानी फौज इन इलाकों को मुक्त कराने में नाकाम रही। बलूचिस्तान, वजीरिस्तान पख्तूनिस्तान पाक से अलग होने के कगार पर हैं। अब भी वक्त है कि पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर ग्रंथि के कैंसर का ऑपरेशन करवा लें और ध्वस्त होते हुए अपने अस्तित्व की हिफाज़त करे, अन्यथा पाकिस्तान 1971 के विभाजन की दास्तान को एक फिर से दोहरा देगा। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एटमी ताकतें हैं। दोनों मिलकर 64 वर्ष पुरानी दुश्मनी को खत्म करके दुनिया के लिए शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, फिर दुनिया के किसी ताकतवर साम्राज्यवादी देश को मौका उपलब्ध नहीं होगा कि भारत-पाक के मध्य दुश्मनी के शोलों को हवा देकर अपनी युद्ध इंडस्ट्री से मुनाफा कमा सके।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

भारतीय कूटनीतिकारों ने किसी हद तक अमेरिकन हुकूमत को यह समझाने में कामयाबी प्राप्त की है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे आईएसआई है, जो अमेरिका से मिलने वाली इमदाद से ही सब कुछ करा रही है।

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission